292

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

अर्चना पुरी से पहले, जे.

सतीश कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

एस. डी. ओ. (संचालन) उप विभाग डी. एच. बी. वी. एन. नरवाना और

अन्य-उत्तरदाता

2016 का सी. आर. सं. 8270

18 दिसंबर, 2023

अभिनिर्धारित किया कि जैसा कि पहले ही पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है, वकील द्वारा यह बयान देकर अपील वापस ले ली गई थी कि वह अपील के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता है। उक्त बयान में, उन्होंने याचिकाकर्ता से प्राप्त ऐसे किसी भी निर्देश के बारे में नहीं बताया था, जो निचली अपीलीय अदालत के समक्ष अपीलकर्ता थे। एक वकील के पास आम तौर पर एक स्वीकार या बयान देने का कोई निहित या स्पष्ट अधिकार नहीं होता है, जो सीधे मुवक्किल के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों को आत्मसमर्पण या समाप्त कर देगा, जब तक कि ऐसा स्वीकार या बयान स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उचित कदम न हो, जिसके लिए वकील को नियुक्त किया गया था। (पैरा 11) ने आगे कहा कि दी गई परिस्थितियों में, विद्वान वकील को बयान देने के माध्यम से अपने मुवक्किल को बांधने का कोई अधिकार नहीं था। जिस अधिकार पर वकील को काम करना है, वह मुवक्किल के कानूनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है, जबकि मुवक्किल के पास यह तय करने का अधिकार है कि लक्ष्य क्या होगा। यदि इस प्रकार दिया गया बयान उन मापदंडों के भीतर आता है, जो मुवक्किल के कानूनी लक्ष्य के हित को सुनिश्चित करते हैं, तो वकील, अपने पक्ष में निष्पादित वकील के अनुसार, अपना बयान देने के अपने अधिकार के भीतर होगा, लेकिन हालाँकि, यदि बयान दिया जाता है, तो मुवक्किल से परामर्श किए बिना, यह वकील की अप्रभावी सहायता का गठन करने की अधिक संभावना है। दी गई परिस्थितियों में, जब सतीश कुमार बनाम एस. डी. ओ. (संचालन) उप-विभाजन डी. एच. बी. वी. एन. को वापस लेने का बयान देने के लिए दिए गए किसी भी प्राधिकरण के बारे में कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है।

293

नरवाना और अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

अपील, जब कोई कारण नहीं दिया जाता है, तो यह वकील द्वारा दिए गए बयान की संभावना को जन्म देता है, विशेष रूप से, उक्त बयान के स्वर और अवधि को ध्यान में रखते हुए।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नवीन गुप्ता ने कहा, प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता अरविंद सेठ।

(1) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में चुनौती निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित दिनांकित 25.05.2016 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश को दी गई है, जिसके तहत, निर्णय और दिनांकित 22.01.2016 डिक्री के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने विद्वान निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित दिनांक 16.09.2016 (अनुलग्नक पी-5) के आदेश को भी चुनौती दी, जिसके तहत अपील की बहाली के लिए एक आवेदन खारिज कर दिया गया है। (2) जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में, प्रत्यर्थियों ने वकील के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई।

(3) पक्षों के विद्वान वकील ने सुना।

(4) पेपरबुक से लिए गए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैंः - (5) कि, शुरू में, याचिकाकर्ता (जो नीचे विद्वत न्यायालय के समक्ष वादी था) ने उत्तरदाताओं (जो नीचे विद्वत न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी थे) के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था, जिससे जाँच रिपोर्ट की वैधता और बाद के ज्ञापन की घोषणा करने की मांग की गई थी, जैसा कि उसमें विस्तृत है, जिसके माध्यम से, Rs.15,55,657/- के जुर्माने का आकलन किया गया था। शिकायत की प्रति अनुलग्नक पी-3 है। उक्त वाद को 22.01.2016 दिनांकित निर्णय और डिक्री के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-6 है। उपरोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता-वादी ने अपील दायर की थी। अपील के लंबित रहने के दौरान, 25.05.2016 पर, याचिकाकर्ता-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने एक बयान दिया था, जो इस प्रकार हैः -

“उन्होंने कहा कि मैं इस अपील के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता। उसी को वापस लेता है। रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाए। ”

(6) इस प्रकार याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि, महसूस कर रहे हैं कि 295

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(10) दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के दावे का दृढ़ता से विरोध किया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में, वकील के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी दाखिल करने के माध्यम से, संबंधित अधिवक्ता को वापस लेने, समझौता करने या गुण-दोष के आधार पर मामले के निपटारे के लिए एक निहित अधिकार दिया गया था। दी गई परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान वकील ने न्यायालय के समक्ष बयान देकर अपील को बहुत सही ढंग से वापस ले लिया था और इन परिस्थितियों में, केवल बयान के इशारे पर, इस तरह से किया गया था कि अपील वापस ले ली गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, अपील की बहाली के लिए कोई मामला नहीं बनाया जाता है। इस प्रकार, पुनर्स्थापना आवेदन को खारिज करने का आदेश, विद्वान निचली अपीलीय अदालत द्वारा सही ढंग से पारित किया गया है। (11) जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, वकील द्वारा यह बयान देकर अपील वापस ले ली गई थी कि वह अपील के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता है। उक्त बयान में, उन्होंने याचिकाकर्ता से प्राप्त ऐसे किसी भी निर्देश के बारे में नहीं बताया था, जो निचली अपीलीय अदालत के समक्ष अपीलकर्ता थे। एक वकील के पास आम तौर पर एक स्वीकार या बयान देने का कोई निहित या स्पष्ट अधिकार नहीं होता है, जो सीधे मुवक्किल के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों को आत्मसमर्पण या समाप्त कर देगा, जब तक कि ऐसा स्वीकार या बयान स्पष्ट रूप से उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उचित कदम न हो, जिसके लिए सतीश कुमार बनाम एसडीओ (ऑपरेशन) उप विभाग डीएचबीवीएन

295

नरवाना और अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

(14) उपरोक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी गई है। रिपोर्टर-डॉ. पायल मेहता